



## केंद्रीय बजट 2025-26

### प्रलिमिस के लिये:

संसद, मखाना, वशीष आरथकि क्षेत्र, मेड इन इंडिया, SMR, परमाणु ऊर्जा अधनियम, परमाणु क्षति के लिये नागरकि दायतित्व अधनियम, उडान योजना, आयकर, लथियम-आयन बैटरी, UPI, ई-शर्म पोर्टल, PM जन आरोग्य योजना, NaBFID, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना, दालों में आत्मनिर्भरता, संशोधनि MSME वर्गीकरण, शहरी चुनौती निधि।

### मेन्स के लिये:

संसाधन आवंटन, आरथकि योजना, राजकोषीय स्थरिता, कल्याणकारी योजनाएँ और राष्ट्रीय वकिस के लिये केंद्रीय बजट का महत्व।

**स्रोत: पी.आई.बी**

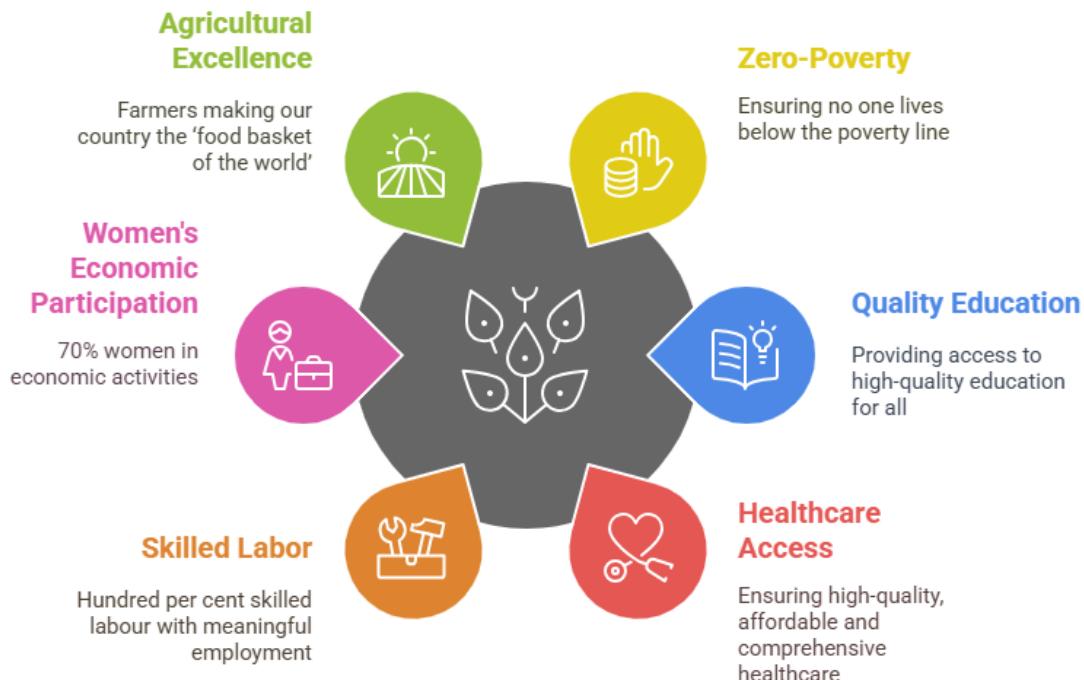
### चर्चा में क्यों?

केंद्रीय वातित मंत्री द्वारा संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया गया, जासिमें वकिस के 4 इंजनों- कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) नविश और नियात को रेखांकति किया गया है।

- ‘सबका वकिस’ लक्ष्य के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में संतुलित वकिस को प्रोत्साहित करना है।
- बजट की थीम के अनुरूप, वातित मंत्री ने वकिसति भारत के व्यापक सदिधांतों को रेखांकति किया है।

//

## Principles of Viksit Bharat



- बजट में गरीबों, युवाओं, कसिनों एवं महलियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों को प्रस्तावित किया गया है।

# केंद्रीय बजट

एक वित्त वर्ष में सरकार को अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण

## अनुच्छेद 112 ( भाग V )

- भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है।

भारत के संविधान में कहीं भी 'बजट' शब्द का उल्लेख नहीं है

## बजट तैयार करने हेतु नोडल निकाय

- बजट प्रभाग ( आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय ) नीति आयोग और संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से

स्वतंत्र भारत का पहला बजट वर्ष 1947 में प्रस्तुत किया गया था।

## बजट के चरण

- प्रस्तुति
- आम चर्चा
- विभागीय समितियों द्वारा जाँच
- अनुदान मांगों पर मतदान
- विनियोग विधेयक पारित करना
- वित्त विधेयक पारित करना



भारत का संविधान बजट के लिये अन्य कौन-से प्रावधान करता है ?

- राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना:
  - अनुदान की मांग नहीं की जा सकती
  - करारोपण वाला कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है
- कानून द्वारा किये गए विनियोग के अलावा भारत की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकता
- संसद की भूमिका:
  - धन/वित्त विधेयक ( कराधान को शामिल करते हुए ) - केवल लोकसभा में प्रदूत किया जाता है
  - अनुदान की मांग पर मतदान - राज्यसभा के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है।
  - धन/वित्त विधेयक - 14 दिनों के भीतर राज्यसभा द्वारा लोकसभा को वापिस भेज दिया जाता है।
    - लोकसभा, राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकता है।

## बजट के प्रमुख घटक

- राजस्व और पूँजी प्राप्तियों का अनुमान
- राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन
- व्यय अनुमान
- समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियाँ/व्यय (+कमी/अधिशेष)
- आने वाले वित्तीय वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीति

वर्ष 2017 तक, भारत सरकार द्वारा 2 बजट पारित किये जाते थे- रेल बजट और आम बजट

## केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजन कौन से हैं?

### पहला ईंजन: कृषि

- परधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना:** इसके अंतर्गत कम कृषि उत्पादकता वाले 100 ज़िलों को शामिल किया गया है, जिससे 1.7 करोड़ कसिान लाभान्वति होंगे, फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाने, सचिवाई की सुवधाओं में सुधार करने का लक्ष्य रखा गया।
  - कौशल, नविश, प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार का समाधान के लिये राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय 'ग्रामीण सम्पन्नता और अनुकूलन नरिमाण' कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा।
- दलहनों में आत्मनिर्भरता:** सरकार तूर, उड्ड और मसूर पर विशेष ध्यान के साथ दालों में आत्मनिर्भरता के लिये एक छह वर्षीय अभियान का शुभारंभ करेगी। जिससे जलवायु-अनुकूल बीज और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होंगे।
  - केन्द्रीय एजेंसियाँ (नेफेड और एनसीसीएफ) अगले चार वर्षों के दौरान कसिानों से मलिने वाली इन तीन दालों को अधिकृतम स्तर पर खरीदने के लिये तैयार रहेंगे।
- कसिान क्रेडिट कार्ड (KCC) की बढ़ी हुई सीमा:** 7.7 करोड़ कसिानों के लिये ऋण की सीमा को सुवधाजनक बनाने के लिये इसे 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया।
- उच्च उपज देने वाले बीजों पर राष्ट्रीय मशिन:** अनुसंधान को मजबूत करना, 100 से अधिक उच्च उपज देने वाली और कीट प्रतरोधी

- बीज कसिमों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- कपास उत्पादकता मशिन: सतत कृषि को बढ़ावा देने, अतिरिक्त लंबे रेशे वाले कपास का उत्पादन बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये 5 वर्ष की पहल।
  - बहिर में मखाना बोर्ड: **मखाना** के उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवरद्धन को बढ़ाने हेतु इसकी स्थापना की जाएगी।
  - फलों और सब्जियों के लिये व्यापक कार्यक्रम: कुशल आपूर्ति शृंखला को बढ़ावा देना और कसिमों के लिये बेहतर बाजार मूल्य सुनिश्चित करना।
  - मत्स्य विकास: भारतीय विशिष्ट आरथिक क्षेत्र और उच्च सागर में **सतत मत्स्य पालन** के लिये नई रूपरेखा, अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप पर ध्यान केंद्रित करना।
  - असम में यूरथिा संयंतर: कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिये ब्रह्मपुत्र घाटी उत्तरक नगिम लिमिटेड (BVFCCL) के परसिर में 12.7 लाख मीटरिक टन क्षमता का एक नया यूरथिा संयंतर स्थापित किया जाएगा।
  - दूसरा इंजन: एमएसएमई
  - संशोधनीय एमएसएमई वर्गीकरण: नविश और कुल कारोबार सीमाओं को क्रमशः 2.5 और दोगुना बढ़ाया गया है, जिससे **लघु उदयम** के लिये ऋण के अवसर बढ़ेंगे।

₹ in Crore	Investment		Turnover	
	Current	Revised	Current	Revised
Micro Enterprises	1	2.5	5	10
Small Enterprises	10	25	50	100
Medium Enterprises	50	125	250	500

- सूक्ष्म उदयम क्रेडिट कार्ड:** 10 लाख सूक्ष्म उदयमों के लिये 5 लाख रुपए की ऋण सुवधा, **वित्तीय समावेशन** और आरथिक भागीदारी को बढ़ावा देना।
  - एमएसएमई के लिये ऋण कवर: गारंटी कवर 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया, जिससे ऋण तक पहुँच बढ़ सकेगी।
  - चमड़ा और फुटवर्पिर के लिये फोकस प्रोडक्ट स्कीम: 22 लाख रोजगार, 4 लाख करोड़ रुपए का राजस्व और 1.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नियमित होगा।
  - खलिना क्षेत्र (TOY)** का विकास: क्लस्टर और नवाचार आधारित विनिर्माण वैश्वकि बाजारों में '**मेड इन इंडिया**' ब्रांड को बढ़ावा दे रहे हैं।
  - राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान: बहिर में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उदयमति और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिससे खाद्य प्रसंस्करण, कौशल और उदयमति को बढ़ावा मिलेगा।
  - स्टार्टअप्स के लिये फंड ऑफ फंड्स: विस्तारित दायरे और **10,000 करोड़ रुपए** के अतिरिक्त योगदान के साथ स्थापित किया जाएगा।
- तीसरा इंजन: नविश**
  - शहरी चुनौती निधि: 'शहरों को विकास केंद्र के रूप में विकसित करने', 'शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास' तथा 'जल एवं स्वच्छता' को समर्थन देने के लिये ₹1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिये ₹10,000 करोड़ आवंटित किये गए।
  - जल जीवन मशिन: कुल बजट परवियय को बढ़ाकर 67,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है तथा इस मशिन की अवधिविषय 2028 तक बढ़ा दी गई है, जिससे गरामीण जल परियोजनाओं के लिये अधिक वित्तिय पोषण के साथ सार्वभौमिक पाइप जलापूर्ति सुनिश्चित होगी।
    - इस मशिन से 15 करोड़ परवियर लाभान्वति हुए हैं, जो भारत की गरामीण आबादी का **80% हसिसा** है।
  - समुद्री विकास निधि: ₹25,000 करोड़ का कोष (सरकार द्वारा 49% योगदान), जहाज निर्माण, **बंदरगाहों** और रसद बुनियादी ढाँचे के लिये दीर्घकालिक वित्तिय पोषण का समर्थन करता है।
  - IIT का विस्तार: **6,500** अतिरिक्त छात्रों के लिये अतिरिक्त बुनियादी ढाँचा, भारत की तकनीकी शक्ति क्षमता को बढ़ावा देगा।
    - PM रसिरच फेलोशिप:** IIT और IIIS में उन्नत अनुसंधान के लिये **10,000 फेलोशिप**।
  - डे केयर कैंसर सेंटर: इन्हें अगले 3 वर्षों में सभी ज़िला अस्पतालों में स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2025-26 तक 200 सेंटर स्थापित किये जाएंगे, जिससे कैंसर उपचार की कफियती उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
  - भारतीय भाषा पुस्तक योजना: इसके तहत स्कूल और उच्च शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने के क्रम में भारतीय भाषा में डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी।
  - विकासित भारत के लिये परमाणु ऊर्जा मशिन: **स्मॉल मॉड्यूलर रेकिक्टरों (SMR)** के लिये **20,000 करोड़ रुपए** के परवियय के साथ इसके तहत वर्ष 2033 तक स्वदेशी रूप से विकासित कम से कम 5 SMR का संचालन किया जाना प्रस्तावित है।
    - परमाणु ऊर्जा अधिनियम** और **परमाणुवीय नुकसान के लिये सविलि दायतिव अधिनियम** में संशोधन के क्रम में नजीब क्षेत्र के साथ सक्रिय भागीदारी के लिये विचार किया जाएगा।
  - UDAN - कृष्टरीय संपरक योजना:** संशोधनीय उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय 120 नए गंतव्यों को शामिल किया जाएगा, जिसका लक्ष्य अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करना है।
    - यह योजना पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों को भी सहयोग प्रदान करेगी।
    - बहिर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट: बहिर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकासित किया जाएगा, साथ ही पटना एयरपोर्ट के विस्तार और बहिरा (पटना) में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा।
    - पश्चिमी काशी नहर ERM परियोजना: मध्यलिंगाचल, बहिर में सचिवाई अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

- रोजगार आधारति वकिस के लयि पर्यटन: देशभर के 50 प्रमुख प्रस्तुत स्थलों को राज्यों के सहयोग से 'चैलेंज मोड' के तहत वकिसति कया जाएगा।
- चौथा इंजन- नरियात संवरद्धन:
  - नरियात संवरद्धन मशिन: क्षेत्रीय और मंत्रालयी लक्ष्यों के साथ एक नरियात संवरद्धन मशिन का शुभारंभ कया जाएगा, जसि वाणिज्य मंत्रालय, MSME मंत्रालय और वतित मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा।
  - भारतट्रेडेनेट (BTN): एक एकीकृत डिजिटिल प्लेटफॉर्म जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दस्तावेजीकरण और वतितपोषण समाधान की सुवधा प्रदान करेगा।
  - गलोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) हेतु राष्ट्रीय ढांचा: उभरते हुए दवतीय शरेणी (टयिर-2) शहरों में आउटसोर्सिंग केंद्रों (Global Capability Centres) को बढ़ावा देने के लयि नीतिगत प्रोत्साहन दयि जाएंगे, जसिसे भारत एक प्रमुख वैश्वकि सेवा प्रदाता के रूप में उभर सके।
  - एयर कारगो के लयि भंडारण सुवधा: उच्च-मूल्य वाले नाशवंत (perishable) उत्पादों के नरियात को सक्षम बनाने के लयि उन्नत भंडारण अवसंरचना का वकिस कया जाएगा, जसिसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक तेज़ और कुशल आपूरति सुनिश्चित हो सके।

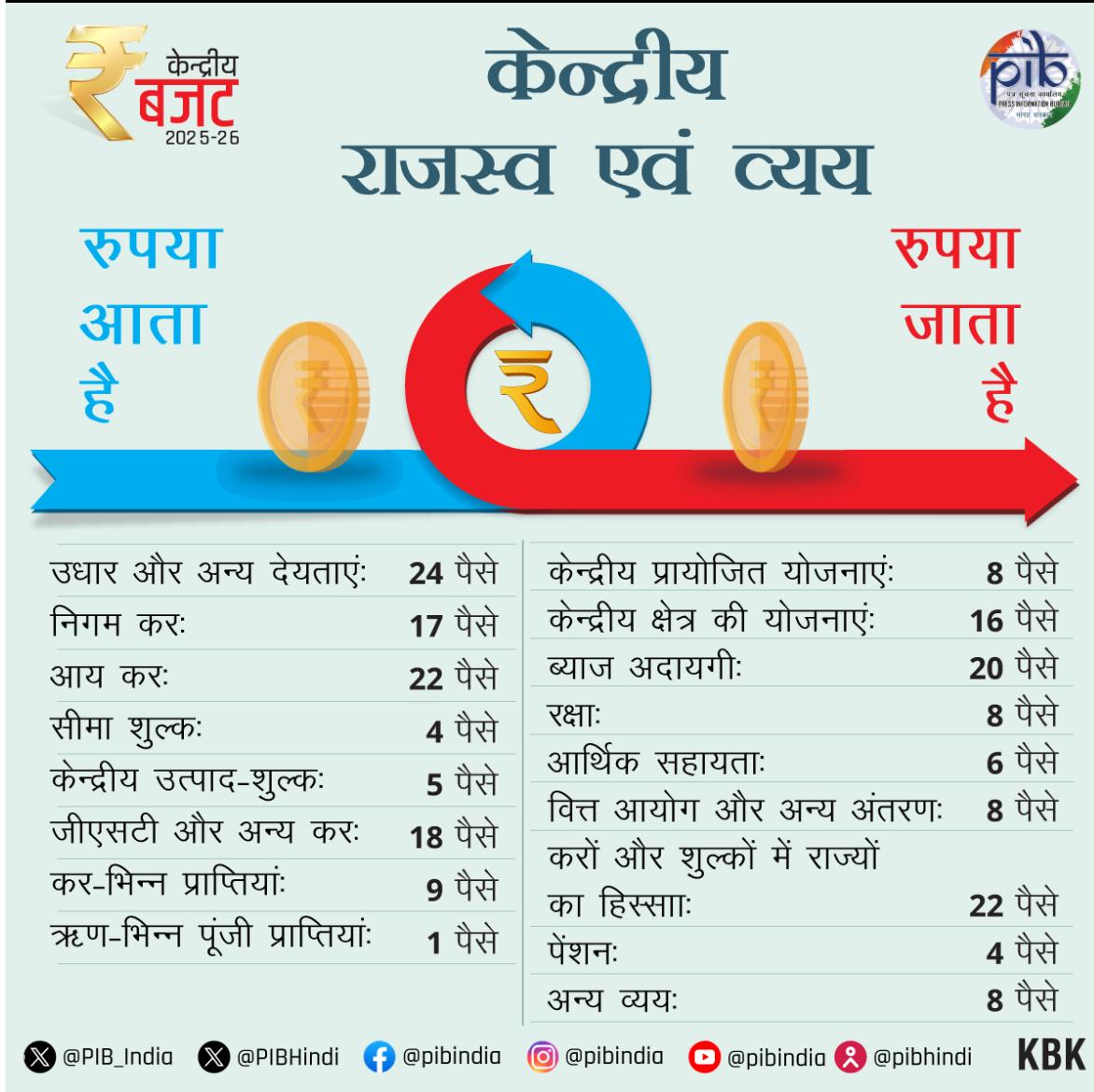
## केंद्रीय बजट 2025-26 की अन्य प्रमुख वशीषताएँ क्या हैं?

- कराधान और वतितीय सुधार:
  - प्रत्यक्ष कर: 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं, छूट के साथ वेतनभोगी करदाताओं के लयि इसे बढ़ाकर 12.75 लाख रुपए कया गया है।

आय (₹ में)	कर की दर
₹0 - ₹4 लाख	शून्य
₹4 - ₹8 लाख	5%
₹8 - ₹12 लाख	10%
₹12 - ₹16 लाख	15%
₹16 - ₹20 लाख	20%
₹20 - ₹24 लाख	25%
₹24 लाख से अधिक	30%

- स्रोत पर कर कटौती (TDS): रेट पर TDS की सीमा को 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कया गया है, जसिसे कर अनुपालन का बोझ कम होगा।
  - कर रटिरन: अद्यतन कर रटिरन की समय सीमा 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई है, जसिसे स्वैच्छकि कर अनुपालन में सुवधा होगी।
  - मूल सीमा शुल्क (BCD) छूट: केंसर, दीर्घकालिक और दुरलभ बीमारियों से संबंधित 36 जीवन रक्षक दवाओं को BCD से पूर्ण छूट दी गई है।
  - घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के क्रम में इलेक्ट्रिक वाहनों एवं मोबाइल उपकरणों हेतु लथियम-आयन बैटरी वनिरिमाण पूंजीगत वस्तुओं को छूट दी गई है।
  - स्थानीय वनिरिमाण को प्रोत्साहित करने तथा आयात पर नरिभरता कम करने के लयि वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से संबंधित घटकों को छूट दी गई।
- सामाजिक कल्यान और समावेशन:
  - पीएम स्वनधि योजना: वतितीय समावेशन को बढ़ावा देने के क्रम में स्ट्रीट वैडर्स के लयि 30,000 रुपए की सीमा वाले UPI -लिंक्ड करेडिट कार्ड का प्रावधान कया गया है।
  - गण वरकर्स के लयि पहचान पत्र: ई-शरम पोर्टल पर पंजीकरण, पीएम जन आरोग्य योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित करने पर प्रकाश डाला गया।
  - 50,000 अटल टकिरगि लैब: नवाचार को बढ़ावा देने के क्रम में इन्हें अगले पाँच वर्षों में सरकारी स्कूलों में स्थापित कया जाएगा।
  - चकितिसा शक्षिका का वसितार: 10,000 नई चकितिसा सीटों के साथ पाँच वर्षों में कुल 75,000 सीटों की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।
- वतितीय क्षेत्र में सुधार:
  - ग्रामीण क्रेडिट स्कोर: यह स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और ग्रामीण उधारकरताओं को औपचारकि ऋण सुवधाओं तक अधिक कुशलतापूर्वक पहुँच प्रदान करने पर केंद्रति है।
    - जन वशिवास वधिक 2.0: इसके तहत 100 से अधिक वधिकि प्रावधानों को गैर आपराधिक शरेणी में शामिल करना, व्यापार संचालन को सुलभ बनाना एवं नयिमक अनुपालन बोझ को कम करना शामिल है।
    - SWAMIH फंड 2.0: यह सरकार, बैंकों और नजी नविशकों के योगदान वाला 1 लाख से अधिक आवास इकाइयों को पूरा करने हेतु ₹15,000 करोड़ का फंड है।
    - बीमा क्षेत्र में FDI: बीमा क्रेडिट में FDI सीमा उन कंपनियों के लयि 74% से बढ़ाकर 100% कर दी जाएगी जनिके द्वारा अपना पूरा प्रीमियम भारत में नविश कया जाता है।
    - राज्यों का नविश मतिरता सूचकांक: यह प्रत्सिप्रद्धि सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के क्रम में राज्यों के लयि एक नया रैंकिंग ढाँचा है।

- ऋण संवरद्धन सुवधा: [NaBFID](#) के तहत बुनियादी ढाँचे हेतु कॉर्पोरेट बॉण्ड का समर्थन करने के क्रम में एकआंशकि ऋण संवरद्धन 'सुवधा' को स्थापित किया जाएगा।
  - ग्रामीण क्रेडिट स्कोर: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु ग्रामीण क्रेडिट स्कोर' ढाँचा तैयार किया जाएगा।
  - पेंशन क्षेत्र: वनियामक समन्वय और पेंशन उत्पादों के विकास के लिये एक मंच स्थापित किया जाएगा।
  - वनियामक सुधारों के लिये उच्च स्तरीय समति: सभी गैर-वित्तीय क्षेत्र के वनियमों, प्रमाणनों और लाइसेंसों की समीक्षा के लिये एक उच्च स्तरीय समति का गठन किया जाएगा।
- राजस्व के प्रमुख स्रोत और व्यय:



- केंद्र सरकार के प्रमुख व्यय (बजट अनुमान):

# कैसे खर्च होगा केंद्र सरकार का पैसा

कुल: 50,65,345

2025-26 के लिए बजट अनुमान, ₹ करोड़ में

ब्याज	12,76,338
परिवहन	5,48,649
रक्षा	4,91,732
प्रमुख सब्सिडी	3,83,407
पेंशन	2,76,618
ग्रामीण विकास	2,66,817
गृह (संघ राज्य क्षेत्र सहित)	2,33,211
कर प्रशासन	1,86,632
कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	1,71,437
शिक्षा	1,28,650
स्वास्थ्य	98,311
शहरी विकास	96,777
आईटी और दूरसंचार	95,298
ऊर्जा	81,174
वाणिज्य और उद्योग	65,553
वित्त	62,924
सामाजिक कल्याण	60,052
वैज्ञानिक विभाग	55,679
विदेश मामले	20,517
पूर्वोत्तर का विकास	5,915
अन्य	4,82,653



वातितीय प्रवृत्तियाँ और बजटीय अनुमान (2023-24 एवं 2024-25) क्या हैं?

- प्राप्तियाँ और व्यय:** वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्तियाँ ₹27.3 लाख करोड़ थीं, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर ₹31.3 लाख करोड़ (BE) हो गई।
  - प्रभावी पूंजीगत व्यय** ₹17.1 लाख करोड़ से घटकर ₹16.3 लाख करोड़ (संशोधित अनुमान) हो गया। राजस्व व्यय ₹34.9 लाख करोड़ से बढ़कर ₹37.0 लाख करोड़ (संशोधित अनुमान) हो गया।
  - पूंजीगत व्यय ₹12.5 लाख करोड़ से बढ़कर ₹15.0 लाख करोड़ (BE)** हो गया, किंतु बाद में इसे संशोधित कर ₹13.2 लाख करोड़ किया गया।
- घाटे की प्रवृत्तियाँ (GDP के प्रतिशत के रूप में):** वातितीय घाटा वर्ष 2023-24 में 3.3% था और वर्ष 2024-25 (संशोधित अनुमान) में यह अपरिवर्तित रहते हुए 3.3% पर बना हुआ है।
  - राजस्व घाटा** वातित वर्ष 2023-24 में 0.3% था, जो वर्ष 2024-25 (संशोधित अनुमान) में मामूली वृद्धिके साथ 0.8% हो गया।
  - प्रभावी राजस्व घाटा** वर्ष 2023-24 में 0.3% था, जो वर्ष 2024-25 (संशोधित अनुमान) में बढ़कर 0.8% पर पहुँच गया।
- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कुल अंतरण:** वातित वर्ष 2023-24 में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कुल ₹20.65 लाख करोड़ अंतरति किये गए।
  - यह आँकड़ा वातित वर्ष 2024-25 (संशोधित अनुमान) में बढ़कर ₹22.76 लाख करोड़ हो गया तथा वर्ष 2025-26 (बजट अनुमान) में इसके और बढ़कर ₹25.60 लाख करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है।
- केंद्र सरकार की नविल प्राप्तियाँ:** वातित वर्ष 2024-25 (संशोधित अनुमान) में केंद्र सरकार द्वारा एकत्रितनविल कर राजस्व ₹28.4 लाख करोड़ रहा, जबकि गैर-कर राजस्व ₹5.8 लाख करोड़ रहा।
  - इसके अतरिक्त गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियाँ (जनिमें वनिविश से प्राप्त राजस्व और ऋणों की वसूली शामिल हैं) वर्ष 2024-25 (संशोधित अनुमान) में ₹0.8 लाख करोड़ रहीं।



₹ करोड़ में	2023-24 (वास्तविक)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (संशोधित अनुमान)	2025-26 (बजट अनुमान)
राजस्व प्राप्तियां	27,29,036	31,29,200	30,87,960	34,20,409
पूँजी प्राप्तियां	17,14,411	16,91,312	16,28,527	16,44,936
कुल प्राप्तियां	44,43,447	48,20,512	47,16,487	50,65,345
कुल व्यय	44,43,447	48,20,512	47,16,487	50,65,345
प्रभावी पूँजीगत व्यय	12,53,111	15,01,889	13,18,320	15,48,282
राजस्व घाटा	7,65,216	5,80,201	6,10,098	5,23,846
प्रभावी राजस्व घाटा	4,61,300	1,89,423	3,10,207	96,654
राजकोषीय घाटा	16,54,643	16,13,312	15,69,527	15,68,936
प्राथमिक घाटा	5,90,771	4,50,372	4,31,587	2,92,598

@PIB\_India @PIBHindi @pibindia @pibindia @pibindia @pibhindi **KBK**

## निष्कर्ष

"सबका वकास" थीम पर आधारित केंद्रीय बजट 2025-26 समावेशी वकास, गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूरण शक्ति और आरथिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के साथ वकिस्ति भारत के लिये एक मज़बूत आधार तैयार करने पर केंद्रित है। युवाओं, महिलाओं, कसिनों और मध्यम वर्ग को प्राथमिकता देते हुए इस बजट का उद्देश्य सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के साथ सतत वकास एवं नजीकी क्षेत्र के निवास को प्रोत्साहित करना है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो ये उपाय भारत को वैश्विक रूप से प्रतिसिद्धि तथा आरथिक रूप से सशक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रसर कर सकते हैं।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

?/?/?/?/?/?/?/?/?:

प्रश्न. "लेखानुमोदन" और "अंतरमि बजट" में क्या अंतर है? (2011)

- स्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान उपयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार "अंतरमि बजट" के प्रावधान का प्रयोग करती है।
- लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है, जबकि अंतरमि बजट में व्यय तथा अवती दोनों सम्मिलित होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

प्रश्न. वित्तीय मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें वृहद आरथिक रूपरेखा विवरण (The Macro Economic Framework Statement) भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख नमिन आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है: (2020)

- (a) चरिकालिक संसदीय परंपरा के कारण
- (b) भारत के संवधान के अनुच्छेद 112 तथा अनुच्छेद 110 (1) के कारण
- (c) भारत के संवधान के अनुच्छेद 113 के कारण
- (d) राजकोषीय उत्तरदायतिव एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के कारण

उत्तर : (d)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/union-budget-2025-26>

